डाक पंजीयन क्रं. मालवा डिविजन/404/2025-27 RNIMPHI/2022/86763

हिन्दी दैनिक

संघर्ष से सिद्धि

खबरों के साथ, हर नजरिये की बात

Sangharshsesiddhi@gmail.com | उज्जैन शुक्रवार 27 मार्च 2026 | वर्ष-04 अंक-230 | पृष्ठ-08, मूल्य-01 रुपये

''स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाओ''

श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी-डॉ. यादव क्षिप्रा, नदी पर निर्माणाधीन घाटों का किया निरीक्षण

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर निर्माणधीन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी जायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अंगारेश्वर और श्री सिद्धवट के मध्य क्षिप्रा नदी पर बन रहे नए घाटों का अवलोकन भी किया।

ये घाट आगामी सिंहस्थ महापर्व-2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान और अन्य सुविधाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित घाटों के लगभग 200 मीटर क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था तथा सुविधाजनक स्थानों पर टॉयलेट बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख घाटों पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर सुविधा घर विकसित करने के निर्देश भी दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घाटों के आसपास श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लगभग 500 मीटर की दूरी पर सीढ़ियाँ या अन्य पहुँच मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, जिससे मुख्य घाटों तक पहुंचना आसान हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री सिद्धवट और श्री अंगारेश्वर मंदिर के बीच निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि पुल के निर्माण से दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन सुगम होगा और श्रद्धालुओं को एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा। घाटों पर स्नान के लिए लगभग 5 मीटर चौड़ा घाट तैयार किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के आने-जाने के साथ बैठने की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घाटों पर श्रद्धालुओं के बैठने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित करने के निर्देश दिए।

इरान युद्ध को लेकर मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक संघर्ष के बीच देश की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य टीम इंडि की भावना से प्रयासों का समन्वय करना है। आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए मुख्य सचिवों के साथ एक अलग सत्र आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे ताकि देश की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जा सके, क्योंकि संघर्ष चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। बैठक में टीम इंडिया की भावना से प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के सीएम आचार संहिता (एमसीसी) के कारण बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि, चुनाव वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए जल्द ही एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होंगे। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चर्चाओं में आकस्मिक योजना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के विषय भी शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में चुनाव करा रहे राज्य आदर्श आचार संहिता के कारण इसमें भाग नहीं लेंगे, और योजना एवं प्रतिक्रिया तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से उनके मुख्य सचिवों के साथ अलग से बातचीत की जाएगी।

देश में तेल, गैस की कोई कमी नहीं, दो महीने के लिए तेल, महीने भर के लिए एलपीजी का सुनिश्चित इंतजाम-सरकार

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस सहित देश में जरूरी पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का तथ्यों के साथ खंडन करते हुए कहा है कि कुछ तत्व जनता को भ्रमित करने के लिए गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि खाड़ी में जारी युद्ध के चार सप्ताह हो रहे हैं फिर भी देश में दो माह के लिए पर्याप्त तेल है। इसके अलावा देश में दैनिक कुल एलपीजी की मांग के 60 प्रतिशत हिस्से का देश में ही उत्पादन हो रहा है तथा बाकी एलपीजी की आपूर्ति विदेशी स्रोतों से निरंतर हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीज़ल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि कि वे जान-बूझकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के एक शरारती और सुनियोजित अभियान से गुमराह न हों। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ पंपों पर घबराहट में खरीदारी की जो इक्कर-दुक्का घटनाएं सामने आईं, वे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो के जरिए जान-बूझकर फैलाई गई गलत सूचनाओं की वजह से हुईं है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी केंद्र है और पेट्रोलियम उत्पादों का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 150 से ज्यादा देशों को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के लिए खुला है-अब्बास अराघची

नई दिल्ली। ईरान ने भारत और कुछ अन्य मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम ने विदेश मंत्री के हवाले से कहा कि तेहरान ने भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान सहित मित्र देशों के जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी है। श्री अराघची ने कहा, हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान सहित मित्र राष्ट्रों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि यह जलडमरूमध्य दुश्मनों और उनके सहयोगियों के लिए बंद है। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग

है, जिसके माध्यम से वैश्विक तेल और गैस व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया था।

श्री अराघची ने कहा, हमारे दृष्टिकोण से, होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से बंद नहीं है। यह केवल दुश्मनों के लिए बंद है। अपने दुश्मनों और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने देने का कोई कारण नहीं है। इससे पहले, ऊर्जा आपूर्ति में वैश्विक व्यवधानों और ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस जलमार्ग को फिर से खोलने का आह्वान किया था। गौरतलब है कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 15-सूत्रीय शांति योजना का उपहास करते हुए उसे खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजरायल खुद से बातचीत कर रहे हैं और ईरान के साथ शांति वार्ता के बारे में श्री ट्रम्प के बयानों को फर्जी बताया।

धार जिले में सहकारिता विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया

रिटायरमेंट नहीं देने और नोटिस के दबाव में प्रभारी प्रबंधक की मौत का आरोप, मृतक की पत्नी ने तीन अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की

धार। जिले के तिरला क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है जहाँ सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर अवैधानिक आर्थिक लाभ और दबाव की राजनीति के चलते एक प्रभारी प्रबंधक की मौत होने के गंभीर आरोप लगे हैं।

मृतक अशोक पाटीदार की पत्नी ने तिरला थाने में आवेदन देकर जिलाउपायुक्त सहकारिता, सोसायटी प्रशासक और जिला सहकारी बैंक प्रबंधक पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।

बताया जा रहा है कि 65 वर्ष की उम्र पार करने के बावजूद मृतक को सेवा निवृत्त नहीं किया गया और बाद में भारी ब्याज की राशि जमा करने का नोटिस देकर दबाव बनाया गयाज जिसके बाद सदमे में उनकी मौत हो गई।

यह है मामला-

बहुउदेशीय प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मर्या तिरला में अशोक पाटीदार प्रभारी प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। तिरला सोसायटी प्रशासक व डीआर एवं प्रबंधक जिला सहकारी बैंक धार की मिली भगत के चलते उम्रदराज व्यक्ति को नोकरी पर रखकर अनैतिक लाभ उठाने के लिए दबाव बनाकर नौकरी पर यथावत रखा गया। जबकि प्रभारी प्रबंधक अशोक पाटीदार की सहकारिता विभाग में जन्म तिथी 1 जून 1961 दर्ज है। वर्तमान में अशोक पाटीदार की उम्र करीब 65 वर्ष हो चुकी थी। जबकि शासन के नियम है कि 62 वर्ष में ही अनिवार्य सेवा निवृति होती है। मृतक अशोक पाटीदार की पत्नि जानीबाई ने प्रशासक व डीआर एवं प्रबंधक जिला सहकारी बैंक धार के विरुद्ध अनैतिक लाभ कमाने के उदेश्य से अनिवार्य सेवा निवृति नही देने का आरोप लगाया है।

डीआर, प्रशासक व बैंक प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप-

तिरला सोसायटी प्रभारी प्रबंधक अशोक पाटीदार जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। मृतक अशोक की पत्नि जानीबाई पाटीदार ने तिरला सोसायटी प्रशासक रमेशचंद पेंडारकर व जिलाउपायुक्त सहकारिता वर्षा श्रीवास एवं प्रबंधक जिला सहकारी बैंक धार केके रायकवार पर पति की मौत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए है। मृतक की पत्नि जानी बाई ने बताया कि मेरे पति अशोकजी की उम्र 65 वर्ष होने के बावजुद विभाग में पदस्थ अधिकारियों ने अनिवार्य सेवा निवृति जानबुझकर नहीं दी। मेरे पति बहुत सीधे व्यक्ति थे। मेरे पति का सेवा काल बिलकुल बेदाग रहा। पुरे कार्यकाल के दौरान उन पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगे थे। उनके सीधे होने का फायदा विभाग के अधिकारियों ने खुब उठाकर आर्थिक शोशण किया। मेरे पति को बिना आधार के अनियमितता का आरोप लगाकर जिला सहाकारी बैंक धार ने 12 मार्च 2026 को पत्र क्रमांक /स्थापना/ 2025-26/4224 द्वारा अनाधिकृत रुप से संस्था की नगदी सिल्लक के ब्याज की राशि 12,63,526 रु तीन दिवस में संस्था के खाते में जमा करने का नोटिस दिया गया। जिसमें मेरे पति अशोक पाटीदार पर अनाधिकृत रुप से राशि उपयोग करने का आरोप लगाया गया। तथा तीन दिवस में उक्त राशि जमा नहीं होने पर पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई। उक्त पत्र कंमांक द्वारा दी गई धमकी एवं अनाधिकृत से राशि गबन का आरोप लगाने से आहत होकर मेरे पति सदमे में आ गए और 15 तारीख की रात में अचानक से मेरे पति की मृत्यू हो गई।

65 वर्ष की उम्र तक रिटायर नहीं कर आर्थिक शोषण किया-

तिरला प्रबंधक मृतक अशोक पाटीदार की बेवा जानी बाई पाटीदार निवासी

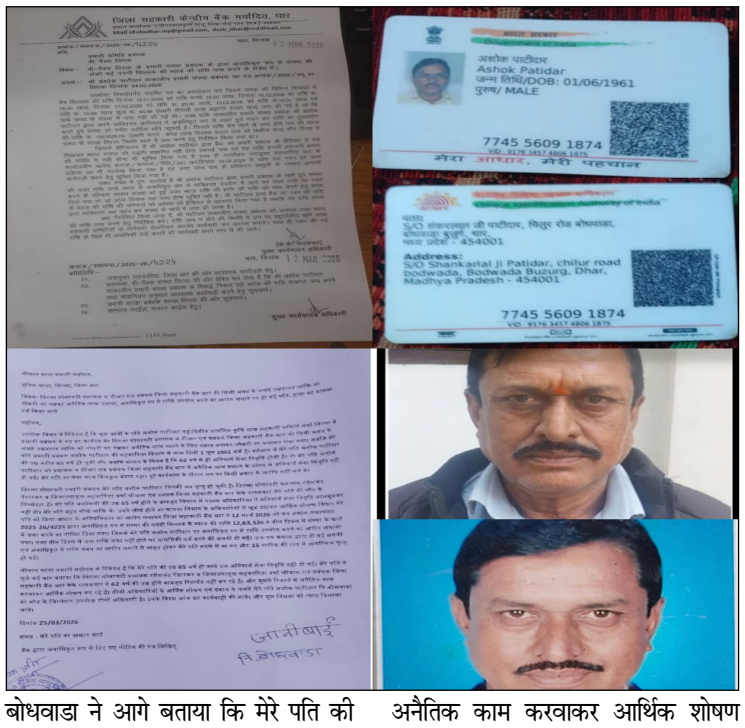

बोधवाडा ने आगे बताया कि मेरे पति की उम्र 65 वर्ष हो जाने तक अनिवार्य सेवा निवृति नही दी गई। मेरे पति ने मुझे कई बार बताया कि तिरला सोसायटी प्रशासक रमेशचंद पेंडारकर व जिलाउपायुक्त सहकारिता वर्षा श्रीवास एवं प्रबंधक जिला सहकारी बैंक धार केके रायकवार रिटार्यड नहीं कर रहे है। और मुझसे रिकार्ड में अनैतिक काम करवाकर आर्थिक शोषण कर रहे है। आर्थिक शोषण एवं दबाव के चलते मेरे पति अशोक पाटीदार नि बोधवाडा की मृत्यु के जिम्मेदार उपरोक्त तीनों अधिकारी है। अशोक पाटीदार की विधवा ने पूलिस थाना तिरला में आवेदन देकर तीनों अधिकारियों के विरुध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

'युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' का मंचन, श्री गुरूजी सेवा न्यास इंदौर द्वारा अभिनव आयोजन

इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित प्रेरक नाट्य 'युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' का मंचन इंदौर में 27-28-29 मार्च को माधव सृष्टि श्री गुरूजी सेवा न्यास, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे इंदौर में प्रतिदिन रात्रि 07 से 09.30 आयोजित होगा। श्री गुरूजी सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस नाटक में डॉ. हेडगेवार के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का प्रदर्शन किया जाएगा।

श्री गुरूजी सेवा न्यास के सचिव संदीप जमींदार ने बताया कि डॉ. हेडगेवार ने भारत की हजारों वर्षों की गुलामी के पश्चात राष्ट्र को संगठित करने का संकल्प लिया था। वे कांग्रेस से जुड़े रहे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर उन्होंने समाज को एकता, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना से जोड़ने का कार्य

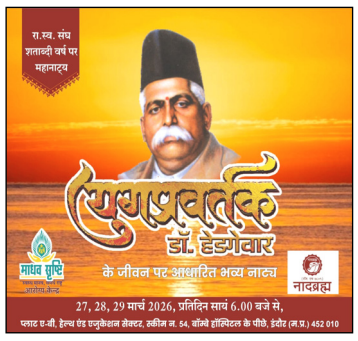

किया।

नाटक 'युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' में उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया जाएगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के गरम दल और अहिंसक विचारधारा के टकराव, हिंदू समाज की निष्क्रियता, डॉ. हेडगेवार पर लगे राजद्रोह के मुकदमे, तिलकजी, योगी अरविंद और सावरकर से प्राप्त वैचारिक प्रेरणाओं को प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से जन्म से लेकर अवसान तक की यात्रा प्रस्तुत की जाएगी ।

नाटक में दिखाया जाएगा कि कैसे डॉ. हेडगेवार ने संगठन के शाश्वत स्थायित्व की परिकल्पना की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। साथ ही सुभाषचंद्र बोस के मन में सैनिकी संगठन की प्रेरणा और संघ के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को भी मंच पर दर्शाया जाएगा। इस नाट्य को नागपुर के सुप्रसिद्ध नाट्य मंच नाद ब्रह्म द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा नागपुर से 50 कलाकारों द्वारा इसका मंचन किया जायेगाद्य मंचन में लाइट, साउंड एवं अत्याधुनिक तकनीक का समावेश किया जायेगा जिससे नाट्य प्रस्तुति जीवंत प्रतीत होगी।

पथरिया-बटियागढ़ आईटीआई भवन निर्माण को मिली स्वीकृति, जल्द शुरू होगा कार्य

दमोह। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पथरिया एवं बटियागढ़ में आईटीआई भवन निर्माण को स्वीकृति मिल गई है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब वे विधायक थे, उसी दौरान दोनों स्थानों पर आईटीआई की स्वीकृति कराई गई थी तथा विभिन्न ट्रेड्स भी प्रारंभ कराए गए थे। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इन संस्थानों के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। राज्यमंत्री श्री पटेल के अनुसार

बटियागढ़ आईटीआई भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ 34 लाख रुपए तथा पथरिया आईटीआई भवन के लिए 14 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। दोनों भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की पीआईयू के माध्यम से कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आईटीआई भवनों के साथ ही 30-30 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी और वे तकनीकी शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि इन आईटीआई भवनों के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को नए-नए ट्रेड्स सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

सलमान खान क्या होंगे गिरफ्तार? अदालत ने पान मसाला विज्ञापन मामले में पुलिस को दिया निर्देश

जयपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में कानूनी घेराबंदी में फंसते नजर आ रहे हैं। जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस की विशेष टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह टीम मुंबई जाकर सलमान खान को वारंट तामील कराए। आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि वारंट की तामील में बाधा उत्पन्न होती है या फिर 6 अप्रैल को सलमान खान के साथ पान मसाला कंपनी के निदेशक राकेश कुमार चौरसिया और दिनेश कुमार चौरसिया आयोग के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं

आयोग के अध्यक्ष जीएल मीणा और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार की पीठ ने पुलिस महानिदेशक के माध्यम से जयपुर पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को यह आदेश जारी किए हैं। यह आदेश परिवादी योगेन्द्र सिंह की ओर से दायर शिकायत पर पारित किया गया है। आयोग ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सेलिब्रिटी स्टेटस किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता है। वारंट की तामील नहीं होना कानून का

मखौल है और इससे उपभोक्ताओं का आयोगों पर विश्वास भी कमजोर होता है।

केसर होने के दावे पर किया मुकदमा

मामले की शुरुआत योगेंद्र सिंह के दायर परिवाद से हुई, जिसमें राजश्री पान मसाला के विज्ञापन पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। शिकायत में कहा गया कि उत्पाद को केसर युक्त बताया जा रहा है, जबकि उसकी कीमत के आधार पर उसमें वास्तविक केसर होना संभव नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है।

इससे पहले भी इस मामले में सलमान खान और पान मसाला कंपनी को राहत नहीं मिली है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने उनकी निगरानी याचिकाओं को खारिज करते हुए भ्रामक विज्ञापन के मामलों में सख्ती के संकेत दिए थे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को यह सिफारिश भी की गई थी कि ऐसे मामलों को केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण तक सीमित न रखकर राज्य उपभोक्ता आयोगों के दायरे में भी लाया जाए।

हकीकत-पलायन रोकने की मनरेगा अब विकसित भारत-जी राम जी योजना का भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा सहारा, पेट पालने के लिए महानगर की ओर कर रहे रुख-मनरेगा की तरह अब विकसित भारत-जी राम जी योजना में भी पलायन की स्थिति जस की तस ही.....

होली के बाद फिर शुरू हुआ पलायन, गांव में काम-दाम न मिलने से महानगरों का कर रहे रुख.....

संजय जैन (सह-संपादक)
942510-1357
883910-7012

गिद्ध दृष्टि

झाबुआ/इंदौर। संजय जैन-सह संपादक। होली का त्योहार संपन्न होते ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरु हो गया है। प्रवासी महानगरों की ओर परिवार सहित

वापसी करने लगे हैं। वहीं विकसित भारत-जी राम जी या अन्य किसी योजना से गांव में परिवार पालने लायक काम न मिलने से युवा भी पलायन की राह पर हैं। रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड पर प्रवासी मजदूर अपने परिवार व गृहस्थी के सामान के साथ बड़ी

संखया में नजर आने लगे हैं।

विकसित भारत-जी राम जी योजना की असलियत सामने आ रही....

जिले से बड़ी सखंया में मजदूरों के पलायन से जहां विकसित भारत-जी राम जी योजना की असलियत सामने आ रही है। वहीं ग्रामीण मजदूरों की दुर्दशा की चिंताजनक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। गांव में कोई काम नहीं है, काम होता भी है तो मजदूरी देर से मिलती है, ऐसे में लोगों से कर्जा लेकर चूल्हा जलाना पड़ता है। ऐसी योजना किस काम की जो न तो काम दे सके न समय पर मजदूरी...?खेत में सिंचाई न होने से इस बार खेती भी सही नहीं है। मजदूरों के गांव में जो काम होते हैं, वे मशीन से कराए जाते है। कभी-कभी पांच-छह दिन काम मिलता है,तो 25 दिन मजदूरों को खाली बैठना पड़ता है। मजदूरों को पैसा मिलने में देर होने से परिवार उनका पेट पालना मुश्किल हो गया है,इसलिए मजदूर पलायन पर जा रहे हैं।

कर दिया रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन .....

विकसित भारत-जी राम जी योजना,2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई सांविधिक संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेता है। रोजगार गारंटी को प्रति ग्रामीण परिवार बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है जिससे आय सुरक्षा सुदृढ़ होगी। चार प्राथमिकता क्षेत्रों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के साथ मजदूरी रोजगार को जोड़ता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार साल 2005 में मनरेगा क़ानून लेकर आई थी,जिसके तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को साल में 100 दिन रोज़गार की गारंटी थी।

विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएं.....

यह विधेयक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवारों को,जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल वाले काम के लिए तैयार हैं,125 दिन की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी देता है। इससे पहले के 100 दिन की पात्रता से अधिक दिनों की आय सुरक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही,बुवाई और कटाई के व्यस्? सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिन का नो-वर्क पीरियड होगा। शेष 305 दिनों में भी मजदूरों को 125 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्राप्त होता रहेगा,जिससे किसानों और मजदूरों दोनों लाभान्वित होंगे। दैनिक मज़दूरी हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में,काम करने की तिथि के 15 दिन के भीतर ही वितरित कर दी जाएगी। रोजगार सृजन को चार प्राथमिकता वाले कार्य-क्षेत्रों के माध्यम से अवसंरचना विकास के साथ जोड़ा गया है।

गांव में काम-दाम न मिलने से महानगरों का कर रहे रुख.....

गांवों से पलायन रोकने के लिए मानव श्रम को ग्राम विकास में भागीदार बनाने के लिए लागू कई योजनाएं भी ग्रामीणों को गांव में काम नहीं दिला पाई हैं। जहां भी काम हुए वहां मानव श्रम की बजाए मशीनों से काम कराए गए जिससे स्थिति बिगड़ती चली गई। ऐसे ही लगातार बदतर हो रहे हालातों से जूझते हुए ग्रामीण अपना घर,खेत-खेलिहान छोडकर शहरों की ओर कूच कर रहे हैं। एक तो विकसित भारत-जी राम जी योजना में गांव में काम ही नहीं मिलते,यदि काम मिल भी जाए तो भुगतान कम और देर से मिलता है। मजदूरी बकाया होने से मजदूर काम करने की बजाय गांव से बोरिया बिस्तर समेटकर काम-दाम और रोटी के लिए महानगरों की ओर पलायन करना ज्यादा सही समझते हैं। ऐसे तमाम कारणों से गांव में काम व मजदूरी के अभाव में जिले से प्रतिदिन सैकड़ों प्रौढ़ और युवा मजदूर रोजगार की तलाश में दिल्ली,मुंबई, चंडीगढ़ सहित अन्य महानगरों का रुख कर रहे हैं।

अब विकसित भारत-जी राम जी योजना भी नहीं रोक पा रही पलायन....

सरकार ने आम गरीबों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानि मनरेगा योजना लागू की थी,जिसके तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को साल में 100 दिन रोज़गार की गारंटी थी। दुनिया की सबसे बड़ी इस योजना का मूल उददेश्य आस्था व श्रम मूलक कार्य कराके लोगों को काम उपलब्ध कराके उनका पलायन रोकना था,मगर ऐसा हो नही सका। सही मायने में अधिकारियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक सभी मनरेगा से मलाई खा रहे थ,वहीं जरूरतमंद ग्रामीण परेशान थैं। सच्चाई ये है कि एक तो 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं थैं,जो कार्य होते भी थैं वे कागजों पर पूर्ण करके राशि आहरित कर ली जाती थी। अब विकसित भारत-जी राम जी योजना भी तालाब गहरीकरण, मिट्टीकरण, पौधरोपण, नाला सफाई के अधिकांश काम मशीनों से कराए जा रहे हैं। कई कामों में मजदूरी तथा मटेरियल के नाम पर फर्जी बिलों से राशि निकाल ली गई है।

VB-GRAM G Act

अब विकसित भारत-जी राम जी योजना से काम देने के निर्देश दिए है....

बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाना अलग बात है। लेकिन पलायन मजबूरी होना अच्छा नहीं है। मैंने गांव में भ्रमण के दौरान व बैठकों में विकसित भारत-जी राम जी योजना के जरिए लोगों को काम देने के निर्देश दिए हैं।

-जितेंद्र सिंह चौहान-सीईओ-जिला पंचायत, झाबुआ

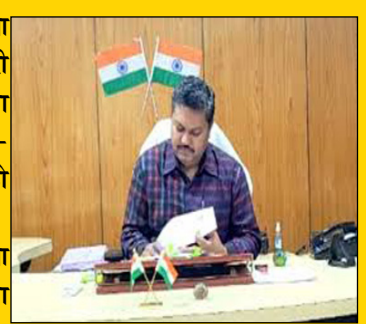

सम्पादकीय

ईरान-ट्रंप के दावे

संयुक्त राष्ट्र को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है, फिर भी यह एकमात्र ऐसी वैश्विक संस्था है जिसके पास हस्तक्षेप करने की वैधता है। यह बेहद ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, इजरायल और ईरान को शामिल करते हुए एक बाध्यकारी प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए; जिसमें सभी पक्ष स्पष्ट रूप से यह वचन दें कि वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की अंतिम घोषित तिथि बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि यह फैसला उनके वरीय सैन्य नेतृत्व की सलाह पर, और साथ ही यूरोपीय देशों और खाड़ी सहकारी परिषद् (जीसीसी) के देशों के दबाव में लिया गया है। इन देशों को डर है कि अमेरिका द्वारा जरूरी अवसंरचना पर बमबारी के बदले में, ईरान डीसेलिनेशन और जल शोधन संयंत्रों को निशाना बना सकता है, जिससे इस इलाके में लाखों लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। यह दावा ध्यान भटकाने की एक तरकीब हो सकती है, हालांकि इस बात की ज़्यादा संभावना है कि अमेरिकी प्रशासन को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य विकल्प की सीमाओं का एहसास होने लगा है। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की बात को कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। लोगों की राय का एक बढ़ता हुआ हिस्सा मानता है कि वह नेतन्याहू के सामरिक एजेंडा से प्रभावित हुए हैं और यह अमेरिका की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस इलाके में विस्तार के एक बड़े ज़ायोनी नज़रिए का हिस्सा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वह 30 मिनट के अंदर लड़ाई खत्म कर सकते हैं। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसा नतीजा सिर्फ़ नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल से ही मुमकिन होगा। यह बयानबाज़ी बहुत चिंताजनक है, खासकर ऐसे नेता की तरफ़ से जिसे जल्दबाज़ी में काम करने वाला और अलग-अलग राय रखने वाला माना जाता है- जो अक्सर अचानक फ़ैसले लेता है, अपने बयान बदलता है, और लंबे समय की कोई सही रणनीति नहीं दिखाता। लगभग तीन हफ़्ते की लड़ाई के बाद अमेरिका और इज़रायल दोनों ही निराश दिख रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ईरान कुछ ही दिनों में हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीदों के उलट, ईरान ने न सिर्फ अमेरिकी-इज़रायली हमले का विरोध किया है, बल्कि खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई भी की है। ईरान के एफ-35 जैसे अतिविकसित लड़ाकू विमान को गिराने की खबरों ने हैरानी और बढ़ा दी है- जिन्हें सिर्फ़ अमेरिका और इज़रायल चलाते हैं। इसके अलावा, ईरान ने हिंद महासागर में 4,000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं, जिससे उसके दुश्मन परेशान हैं। डिमोना नाभिकीय संयंत्र समेत संवेदनशील जगहों के पास हाल के हमलों ने इज़रायल की चिंता बढ़ा दी है। यह युद्ध एक बार फिर इज़रायली सरकार की मानवीय नियमों और अन्तरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी को दिखाता है। बच्चों समेत आम लोगों को हमलों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है, जबकि ज़रूरी अवसंरचना को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया गया है। गाजा में हुई तबाही और लेबनान में दुश्मनी का बढ़ना इस रूझान को और मज़बूत करता है। साथ ही, खाड़ी देश अमेरिका के सुरक्षा भरोसे की कमियों को तेजी से पहचान रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका भी बढ़ते अकेलेपन का सामना कर रहा है। नाटो ने कथित तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में शामिल होने से मना कर दिया है।

बीमार होना पड़ेगा भारी, 1 अप्रैल से 1000 दवाएं होंगी महंगी, छोटी-बड़ी बीमारियों पर होगा असर

1 अप्रैल 2026 से दर्द की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं और बुखार कम करने वाली कई जरूरी दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) में शामिल 1000 से ज्यादा दवाओं के दामों में मामूली बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है।

यह बढ़ोतरी Wholesale Price Inde& (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एनपीपीए ने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में डब्ल्यूपीआई में पिछले साल की तुलना में 0.64956 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी आधार पर इन दवाओं की कीमतों में करीब 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है। यह बढ़ोतरी हर साल नियमित रूप से की जाती है ताकि दवा कंपनियां बढ़ती लागत को कुछ हद तक संभाल सकें। समायोजित कीमतें NLEM की 1000 से अधिक दवाओं पर लागू होंगी।

किन दवाओं पर असर पड़ेगा?

इस बढ़ोतरी से कई आम दवाएं प्रभावित होंगी। इनमें दर्द निवारक दवाएं जैसे पैरासिटामॉल शामिल हैं। बुखार और सिरदर्द में इस्तेमाल होने वाली यह दवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाएं जैसे एजिथ्रोमाइसिन (बैक्टीरियल संक्रमण के लिए) और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी महंगी होंगी। एनीमिया (खून की कमी) की दवाएं, विटामिन और मिनरल्स की दवाएं, कोविड-19 मरीजों के लिए कुछ दवाएं और स्टेरॉयड्स भी महंगी हो जाएंगी। ये सभी दवाएं आम आदमी के रोजमर्रा के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। दवा उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, कुछ दवाओं में दामों में थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, जैसे पैरासिटामॉल में 25 प्रतिशत और सिप्रोफ्लॉक्सासिन में 30 प्रतिशत तक का इजाफा बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से यह 0.6 प्रतिशत के आसपास है।

क्यों बढ़ाई गई कीमतें?

दवा कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) और सॉल्वेंट्स की कीमतें 30-35 प्रतिशत तक

बढ़ गई हैं। ग्लिसरीन की कीमत में तो 64 प्रतिशत का उछाल आया है। पैकेजिंग मटेरियल जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड और एल्युमिनियम फॉइल भी 40 प्रतिशत महंगे हो गए हैं। एक फार्मा लॉबी के प्रतिनिधि ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हर तरल दवा जैसे सिरप और ड्रॉप्स में इस्तेमाल होने वाले ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल और सॉल्वेंट्स महंगे हो गए हैं। इंटरमीडिएट्स की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस बढ़ोतरी से ज्यादा राहत चाहिए। हम एनपीपीए के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

दवा उद्योग का कहना है कि इनपुट लागत बढ़ने से उनकी मुनाफा मार्जिन पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए यह मामूली बढ़ोतरी उन्हें कुछ राहत देगी, लेकिन वे मानते हैं कि यह काफी नहीं है।

उपभोक्ताओं पर असर?

यह बढ़ोतरी आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाएगी। भारत में लाखों लोग रोजाना इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इसका ज्यादा असर महसूस होगा।

हालांकि, बढ़ोतरी सिर्फ 0.6 प्रतिशत है, जो बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जब हजारों दवाएं प्रभावित हों तो कुल मिलाकर खर्च बढ़ सकता है। एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव सिर्फ एनएलईएम में शामिल दवाओं पर लागू होगा। गैर-जरूरी या ब्रांडेड दवाओं की कीमतें बाजार के अनुसार ही रहेंगी। कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के इन नई कीमतों को लागू कर सकेंगी।

दवा उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान युद्ध जैसी ग्लोबल घटनाओं ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। इससे कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत दोनों पर असर पड़ा है। एनपीपीए हर साल डब्ल्यूपीआई के आधार पर कीमतों की समीक्षा करती है ताकि दवाएं उपलब्ध रहें और उद्योग भी टिके रहे। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे डॉक्टर की सलाह से ही दवाएं लें और जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें। कुछ दवाओं के जेनेरिक वर्जन सस्ते हो सकते हैं, इसलिए ब्रांड के बजाय जेनेरिक नाम से दवाएं भी ले सकते हैं। सरकार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए एनपीपीए के जरिए काम करती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी दवाएं आम आदमी की पहुंच में रहें। इस साल की बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी कम है, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली यह छोटी सी बढ़ोतरी दवा उद्योग की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर की गई है। हालांकि, आम आदमी को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगी कि दवाएं बाजार में उपलब्ध रहें। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वे इस मामले पर नजर रखेंगे ताकि आम आदमी को ज्यादा परेशानी न हो।

आज होगा रामघाट पर श्री राम स्तुति कार्यक्रम

उज्जैन। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ की पत्नी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रसाद स्वरूप, माता कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को, और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। रामलला के प्राकट्य उत्सव को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह धार्मिक नगरी उज्जैन में भी राम लक्ष्मण और मां सीता वनवास के समय पधारे थे। तब प्रभु श्री राम ने मोक्ष दायिनी मां क्षिप्रा के तट पर राजा दशरथ का पिंड दान किया था। उस समय से ही तट को रामघाट के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि राम ने ही अपने हाथों से रामेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी।

ऐसे पावन स्थल रामेश्वर महादेव स्थित श्रीराम मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार कर स्वर्णिम भारत मंच के तत्वाधान में तीन दिवसीय राम प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। जिसमें प्रथम दिन स्वस्तिक वाचन कर मां क्षिप्रा का पूजन अर्चन किया गया। दूसरे दिन सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ। आज तीसरे दिन राम स्तुति कार्यक्रम एवं कन्या पूजन के बाद राम प्रसादी भंडारा का आयोजन किया जाएगा।

बैंक परिसर में महिला ने ब्लेड से काटकर उड़ाए 1 लाख रुपये

राजेश नाहर 9479973888

खेतिया। खेतिया के समीप ग्राम मोरतलाई निवासी एक किसान के साथ बैंक परिसर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित ओंकार जाधव के अनुसार, वह 26 मार्च 2026 को अपने बेटे प्रदीप के साथ बैंक में करीब 1 लाख रुपये जमा कराने पहुंचा था।

बताया गया कि किसान अपने साथ एक थैले में 1,00,000 रुपये और 5,000 रुपये ब्याज के लिए निकालकर लाया था। बैंक में वह विड्रॉल फॉर्म भर रहा था, इसी दौरान उसके पास एक अज्ञात महिला खड़ी थी। किसान ने रुपये से भरा थैला अपने कंधे पर टांग रखा था। जब उसने काउंटर पर

पर्ची देने के लिए थैला खोलकर देखा तो उसमें रखे 1 लाख रुपये गायब थे। जांच करने पर पता चला कि थैले को किसी तेज धारदार ब्लेड से काटा गया था और उसमें से रुपये निकाल लिए गए थे। थैले में 500-500 रुपये के दो बंडल रखे हुए थे, जो चोरी हो गए। घटना के बाद किसान ने आसपास महिला की तलाश की, लेकिन वह मौके से फरार हो चुकी थी। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ थाने पहुंचा और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके।

राणा सागर तालाब से वर्षो से हो रही पानी की चोरी...?

पंकज गोस्वामी

राणापुर। स्थानीय बस स्टैण्ड पर एतिहासिक धरोहर राणा सागर तालाब की दूसरी ओर के भाग से खुलेआम वर्षो से पानी चोरी मोटर लगा कर की जा रही इस संबंध में पूर्व में भी समाचार प्रकाशित किए ओर तत्कालीन सीएमओ श्री पाटीदार ओर तत्कालीन तहसीलदार को भी अवगत कराया लेकिन पानी चोरी को रोकने की कोशिश किसी के द्वारा नहीं की गई जिसके चलते पानी चोरी करने वालो के हौसले बुलंद हो चले है। सूत्रों की माने तो राणा सागर तालाब का पानी खेतों में उपयोग वर्षो से लिया जा रहा है इसकी नगर परिषद के द्वारा न तो कोई नीलामी की न कोई शुल्क जमा कराया जा रहा जबकि अवैध रूप से पानी चोरी कर आर्थिक लाभ संबंधितों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। गर्मी में सिंचाई के लिए पानी चोरी होने से पानी कम होकर बदबू मारता है और मच्छर इत्यादि भी पनपते है जबकि तालाब की चारों ओर रहवासी बस्ती होकर उनमें निवास करने वालो के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है वैसे भी नगर परिषद के द्वारा कई वर्षों से तालाब की सफाई नहीं करवाई ओर न जल कुंभी हटाई जो लगातार पूरे तालाब में फैल गई ओर इसके कारण कीड़े मकोड़े भी पनप रहे ओर जहरीले जानवरों का भी भय बना रहता है।

आपको बतादे एक समय वह था जब गांव के लोग इस तालाब में नहाते थे और कपड़े भी धोते थे आज तो इस तालाब में गटरों का पानी मिल रहा है जिससे बदबू फैल रही ओर आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल होकर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।

स्थानीय प्रशासन ओर जिला प्रशासन राणा सागर तालाब में अवैध पानी चोरी को रोके ओर मोटरों को जब्त कर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करे।

स्वच्छ गंगा का संदेश लेकर गंगोत्री से गंगासागर जा रही अखण्ड गंग ज्योत यात्रा पहुंची गंगा द्वार

(रविन्द्र गुप्ता)

वाराणसी। गंगा हमारी आस्था ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है , स्वच्छ गंगा का संदेश लेकर गंगोत्री से गंगासागर तक रन फॉर गंगा रोलर स्केट्स के माध्यम से करते हुए काशी की बेटी सोनी चौरसिया के नेतृत्व में सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अखंड गंग ज्योत यात्रा गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर पहुंची।

ललिता घाट पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में टीम ने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया।

यह यात्रा 8 मार्च-अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को शुरू हुई है जो रोलर स्केट्स के माध्यम से विभिन्न शहरों-कस्बों, गांवों में लोगों को गंगा की सफाई और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरुक करते हुए 3 अप्रैल को गंगासागर तक जाएगी।

इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नमामि गंगे टीम के साथ यात्रा दल ने स्थानीय नागरिकों श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों के साथ गंगा स्वच्छता की अलख जगाई। गंगा तट की स्वच्छता की गई।

लोगों से गंगा किनारे जिंदगी न करने का आवाह्न किया गया । सनातनी गंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण कुमार आयोजन के दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे । अखंड गंग ज्योत यात्रा का स्वागत करते हुए गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा बचाओ-खुशहाली लाओ गंगा की साफ-सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की अलख जगाने के लक्ष्य को इस यात्रा के माध्यम से रखा गया है। इस दौरान लोगों से संवाद किया जाएगा और उन्हें गंगा नदी की महत्ता बताते हुए जलीय जीव जीवन के संरक्षण और उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी।

आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से गंग ज्योत यात्रा का नेतृत्व कर रहीं सोनी चौरसिया, नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला, कैप्टन प्रवीण कुमार, राजेश डोंगरा, विवेक डोंगरा प्रशांत स्केट्स दल के सदस्य मौजूद रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री द्वारा पेटलावद क्षेत्र में जल संसाधन की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया

दीपेश पडियार

पेटलावद/झाबुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा पेटलावद क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं कानाकुआं तालाब एवं रामगढ़ बैराज के निर्माण कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में कानाकुआं तालाब परियोजना के अंतर्गत 435.05 लाख की लागत से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके पूर्ण होने पर लगभग 155 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं रामगढ़ बैराज परियोजना 379.40 लाख की लागत से निर्मित की जाएगी, जिससे लगभग 235 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। इस अवसर पर मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए जल संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पानी ही खेती की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, बल्कि वर्षा जल का बेहतर संचयन भी संभव हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि कानाकुआं तालाब एवं रामगढ़ बैराज जैसे निर्माण कार्य से क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे किसानों को समय पर सिंचाई उपलब्ध होगी, फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी तथा कृषि पर निर्भर परिवारों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही, यह परियोजनाएं भूजल स्तर को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होंगी। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि राज्य शासन द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई जैसे मूलभूत क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

देवास जिले की पीपलरावा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक

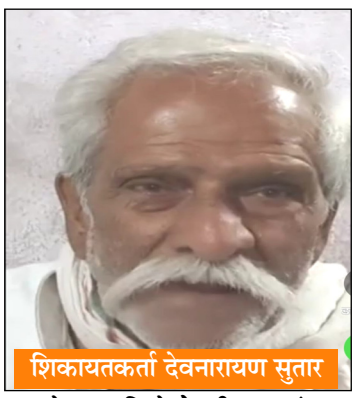
शिकायतकर्ता देवनारायण सुतार

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

कार्यालय नगर परिषद

देवास। जिले के पीपलरावां नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर इंदौर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

2022 के निकाय चुनाव में गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। अब वे अगली सुनवाई (4 अप्रैल) तक वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकेंगे। कारण 2022 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए चुनाव के बाद सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी न करना। प्रभाव अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अब कोई भी वित्तीय स्वीकृति या लेनदेन नहीं कर पाएंगे। याचिका स्थानीय निवासी देवनारायण टेलर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कलेक्टर का रुख देवास कलेक्टर ने कहा कि न्यायिक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है और उच्च कार्यालय को सूचित किया गया है।

अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही में शराब और आरोपी गिरफ्तार

आशीष वाणी

आलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर रघुवंशसिंह के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब की गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, थाना बखतगढ चौकी छकतला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बडी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण एवं कार्यवाही- दिनांक 25 मार्च 2026 को चौकी छकतला पुलिस को मुखबिर के माध्यम से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोन्दवानी के कालाखेत फलिया में एक व्यक्ति अपने निवास के समीप अवैध शराब बडी मात्रा में संगृहित कर उसे अन्यत्र ले जाने की फिराक में है। सूचना पर गंभीरता से त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी बखतगढ के नेतृत्व मे पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर दबिश दी।

दबिश कार्यवाही के दौरान आरोपी हुकला उर्फ मुकेश (पिता तेलिया वास्केल), निवासी ग्राम गोन्दवानी से पूछताछ कर तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 63 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब एवं बीयर बरामद की गई। जब्त की गई मदिरा का विवरण निम्नानुसार है-

● गोवा विस्की-43 पेटी (516 बोतल) ● माउन्ट बीयर-10 पेटी (240 केन) ● लंदन प्राईड विस्की व वोदका-06 पेटी (192 क्वार्टर एवं 24 बोतल) ● एमडी विस्की-04 पेटी (192 क्वार्टर) पुलिस द्वारा कुल 594.12 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसका बाज़ार मूल्य लगभग 1,80,500 रुपये (एक लाख अस्सी हजार पाँच सौ रुपये) है। आरोपी द्वारा उक्त मदिरा के भंडारण हेतु कोई भी वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) या परमिट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, उसके विरुद्ध थाना बखतगढ़ में अपराध क्रमांक 44/2026, धारा 34(2) एवं 36 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी बखतगढ़ निरीक्षक संतोष सिसोदिया, चौकी प्रभारी छकतला उप-निरीक्षक राहुल चौहान, सउनि लक्ष्मण परमार, सउनि अमर सिंह जूनवाल, आरक्षक दिनेश रावत, चंदन चौहान, सुनील सिसोदिया, गोविंद यादव एवं जगदीश जामोद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

MP में हथियारों की तस्करी का बड़ा खुलासा-10 पिस्टल-13 मैगजीन और जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, यहां होने वाली थी सप्लाई

इंदौर। मध्यप्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियारों की खरीद-फरोख्त करते 4 आरोपियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि फोरलेन पर सप्लाई होने वाली थी।

आरोपियों के कब्जे से 10 देशी पिस्टल, 13 मैगजीन, जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार द्विवेदी और एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी मानपुर महेंद्र मकासरे और उनकी टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग फोरलेन के पास हथियारों की डील करने आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और लेबड़-मानपुर फोरलेन स्थित तुलसी चिनार ग्रीन पार्क कॉलोनी के पास चारों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों शिवम तोमर निवासी मुरैना, कार्तिक लसोरिया निवासी इंदौर, राजू छाबड़ा निवासी धार, भगत सिंह दांगी निवासी धार तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 10 देशी पिस्टल 13 मैगजीन 6 जिंदा कारतूस 5 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल एक बैग कुल करीब 4 लाख 23 हजार रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी हथियारों की तस्करी कर इंदौर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और दूसरे आरोपी पर एनडीपीएस और मारपीट के केस दर्ज हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ मानपुर थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए थे और किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे। इंदौर ग्रामीण पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है।

डबरा नगर पालिका के पूर्व सीएमओ प्रदीप भदौरिया पर EOW ने दर्ज की एफआईआर, रिश्वत लेकर हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने का आरोप

ग्वालियर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने वाले डबरा नगर पालिका के पूर्व सीएमओ प्रदीप भदौरिया पर एफआईआर दर्ज की है, उनपर आरोप है कि उन्होंने बिना जियो टैगिंग किये रिश्वत लेकर हितग्राहियों के खातों में निर्धारित राशि से अधिक अनुदान राशि देकर शासन को 1,31,50,000 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है, इस भ्रष्टाचार की शिकायत वार्ड क्रमांक-11 के पार्षद धर्मेन्द्र सिंह हैप्पी ने की थी।

ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक दीदार कालोनी झांसी रोड डबरा ग्वालियर निवासी वार्ड नम्बर 11 के पार्षद धर्मेन्द्र सिंह हैप्पी ने EOW मुख्यालय भोपाल में डबरा नगर पालिका के पूर्व सीएमओ प्रदीप भदौरिया के विरुद्ध शिकायत की थी, शिकायती आवेदन में धर्मेन्द्र सिंह हैप्पी ने पूर्व सीएमओ भदौरिया पर 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 के बीच पीएम आवास योजना में घोटला करने के आरोप लगाये।

पार्षद धर्मेंद्र सिंह हैप्पी ने आरोप लगाया कि प्रदीप भदौरिया ने हितग्राहियों के

लिए शासन द्वारा निर्धारित 2.50 लाख रुपये के स्थान पर सांठ गांठ कर रिश्वत लेकर बिना जियो टैगिंग के कई हितग्राहियों के खातों में 3 लाख रुपये की राशि डाल दी, मुख्यालय ने शिकायत दर्ज कर ग्वालियर EOW को जांच के भेज दिया।

बिना जियो टैगिंग हितग्राहियों के खातों में डाली अधिक राशि

ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने मामले की जांच की तो पाया क प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही को कुल 2,50,000 रुपये की राशि तीन किश्तों में दी जानी निर्धारित है लेकिन इसके विपरीत सीएमओ और स्टाफ ने 13 चिन्हित हितग्राहियों के खातों में नियम विरुद्ध तीन-तीन लाख रुपये की राशि पोर्टल के माध्यम से डाल दी। उन्होंने बिना नोटशीट चलाये और बिना जियो टैगिंग किये सीधे PPA जारी कर भुगतान कर दिया।

शासन को 1 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति

जांच में सामने आया कि तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने संविदा कर्मचारी राहुल गुप्ता को नियम विरुद्ध पोर्टल संचालन और भुगतान प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया था, दोनों ने मिलकर और रिश्वत लेकर हितग्राहियों को निर्धारित राशि से अधिक अनुदान राशि का भुगतान किया गया एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना बिना भौतिक सत्यापन किये यानि बिना जियो टैगिंग के ही राशि 1,31,50,000 रुपये का आहरण कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई।

पूर्व सीएमओ और कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

जांच के बाद ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता, संविदाकर्मी नगर पालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर के विरूद्ध धारा 409, 120बी भा.द.वि. एवं धारा 7, 13 (1) क सहपठित 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया है ।

रेल प्रोजेक्ट लाने के के लिए कांग्रेस ने की थी सार्थक पहल भाजपा के नेता श्रेय लेने में लग गए है-स्वतंत्र जोशी अध्यक्ष धार जिला कांग्रेस

धार। आज राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच, माधवराव सिंधिया जी और जमुना देवी जी के प्रयासों और डॉ. मनमोहन सिंह के सहयोग से साकार हुए धार क्षेत्र के रेलवे प्रोजेक्ट का टेस्टिंग किया जा रहा है।

आने वाले समय में भाजपा एवं उनके नेताओं द्वारा उद्घाटन की बात की जा रही है, जिसका श्रेय आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेने का प्रयास कर रही है।

धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने बताया की यह सर्वविदित है कि धार में रेलवे लाने की परिकल्पना सबसे पहले राजीव गांधी जी ने की थी।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री रहते हुए माधवराव सिंधिया जी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की और लगातार प्रयास किए। आगे चलकर डॉ. मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इस परियोजना को स्वीकृति मिली, बजट आवंटित हुआ तथा झाबुआ में इसका उद्घाटन भी किया गया।

आज जब यह सपना पूरी तरह साकार हुआ है, तो यह कांग्रेस की वर्षों की मेहनत, दूरदृष्टि और जनहित के प्रति समर्पण का परिणाम है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के नेतागण इस ऐतिहासिक परियोजना का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इसकी नींव कांग्रेस के नेतृत्व में रखी गई थी। यह कांग्रेस की विचारधारा और जनसेवा की जीत है।

पेटलावद में ओली जी पर्व के दौरान सिद्ध प्रभु की आराधना में जुटे श्रावक

दिपेश पड़ियार

पेटलावद। जैन धर्म के पवित्र शाश्वत ओली जी महापर्व के दूसरे दिन आज आराधकों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ णमो सिद्धाणं पद की विशेष आराधना की। प्रथम दिन णमो अरिहंताणं पद की आराधना के पश्चात आज सिद्ध प्रभु का स्मरण करते हुए तपस्वियों ने अपनी साधना को आगे बढ़ाया।

इस आध्यात्मिक आयोजन में समाज के हर वर्ग का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के श्रद्धालु अपनी शक्ति अनुसार आराधना और सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज की तपस्या में कुल 66 तपस्वियों ने भाग लिया, जिसमें साधना की अलग-

अलग श्रेणियों का समावेश रहा। विशेष रूप से वर्ण के 8, बिना नमक के 4 और नमक वाले 54 आयंबिल तप के साथ श्रद्धालुओं ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयास किया। आज के इस पावन आयोजन एवं प्रभावना के पुण्यशाली लाभार्थी पेटलावद का आर. आर. ग्रुप रहा, जिनके सहयोग से धर्म प्रभावना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भक्तिमय वातावरण के बीच आराधना का यह क्रम निरंतर जारी है।

श्योपुर तहसीलदार अमिता सिंह गिरफ्तार-बाढ़ राहत घोटाले में कोर्ट ने भेजा जेल, KBC से सुर्खियों में आई थी

श्योपुर। मध्य प्रदेश प्रदेश के श्योपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें महिला जेल भेजा गया है। यह पूरा मामला साल 2021 में बाढ़ राहत घोटाले से जुड़ा हुआ है। महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को ग्वालियर निवास से बड़ौदा पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें शिवपुरी की महिला जेल भेजा गया है। दरअसल, अमिता सिंह पर 2021 में श्योपुर जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप है। जांच में 2.57 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ था।

इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार बड़ौदा अमिता सिंह तोमर मुख्य आरोपी हैं। कुल 110 लोग आरोपी हैं, जिनमें 28 पटवारी भी शामिल हैं।

आरोप है कि राहत राशि के वितरण में फर्जीवाड़ा किया गया और बाढ़ पीड़ितों को उनका हक नहीं मिला।

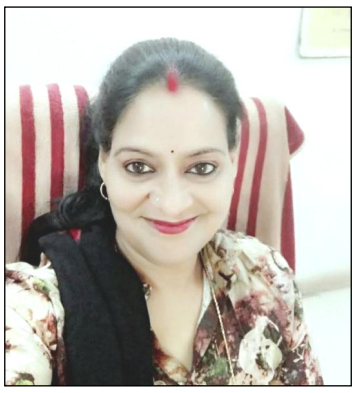

KBC फेम से सुर्खियों में आई थीं अमिता सिंह

अमिता सिंह तोमर साल 2011 में 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) सीजन-5 में भाग लेकर 50 लाख रुपये जीते थे। वे 'KBC वाली मैडम' के नाम से प्रदेश में चर्चित रहीं। वर्तमान में वे श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में तहसीलदार पद पर तैनात हैं। उपभोक्ता संगठन और स्थानीय लोग लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जांच एजेंसी और पुलिस तेजी से कार्रवाई कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। SC ने स्पष्ट कहा था कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। इस फैसले के बाद अमिता सिंह तोमर की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज हो गई थी। आपको बता दें कि विशेष न्यायालय श्योपुर और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच से पहले ही उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी।

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपीगणों को भानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमती हेमलता कुरील एवं एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक आर.सी. दांगी के कुशल नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 08.03.2026 को सूचनाकर्ता मनीष पिता अशोक राठौर, उम्र 35 वर्ष, निवासी लोटखेड़ी गेट भानपुरा द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता अशोक पिता रामगोपाल राठौर, उम्र 60 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

सूचना पर थाना भानपुरा में मर्ग क्रमांक 14/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया एवं भौतिक साक्ष्य जप्त किए गए। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण हैंगिंग (फांसी) बताया गया।

मृतक के पास से प्राप्त सुसाइड नोट तथा परिजनों (मनीष राठौर) एवं स्वतंत्र साक्षी (कमल राठौर) के कथनों के आधार पर यह पाया गया कि समाज के अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान लेखा-जोखा एवं आय-व्यय के विवाद को लेकर आरोपीगण द्वारा मृतक को लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा रुपये-पैसे की मांग कर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी प्रताड़ना से त्रस्त होकर मृतक द्वारा आत्महत्या किया जाना पाया गया।

अपराध पंजीबद्ध

मर्ग जांच के दौरान मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का पाए जाने से अपराध क्रमांक 66/2026 धारा 108, 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

गिरफ्तारी की कार्यवाही

विवेचना के दौरान आरोपीगण- मंगल सिंह पिता सुपारीलाल राठौर, उम्र 54 वर्ष जितेन्द्र उर्फ मोनू पिता मंगल सिंह राठौर, उम्र 35 वर्ष निवासी लोटखेड़ी गेट भानपुरा को दिनांक 25.03.2026 को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों को विगत रात्रि में मुखबिर की सूचना पर राजस्थान सीमा क्षेत्र में लेडी चौराहे से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ की गई। तत्पश्चात आरोपियों को माननीय न्यायालय भानपुरा में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेशानुसार उपजेल गरोठ भेजा गया।

फरारी के दौरान गतिविधियां

ज्ञातव्य हो कि आरोपी मंगल सिंह राठौर आदतन अपराधी है, जो गिरफ्तारी से बचने हेतु नावली, गांधी सागर, चेचट, रामगंजमंडी, रावतभाटा, कोटा एवं झालावाड़ आदि क्षेत्रों में अज्ञात स्थानों पर छिपा रहा।

केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। केंद्रीय विद्यालय मंदसौर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यालय प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बाल वाटिका-1, बाल वाटिका-3 एवं कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं अंतिम सूची का प्रदर्शन 8 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 16 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी। बाल वाटिका-2, कक्षा 2 एवं अन्य कक्षाओं के लिए पंजीकरण 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए चयन सूची 13 अप्रैल 2026 को जारी होगी तथा प्रवेश प्रक्रिया 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक संपन्न की जाएगी। विद्यालय प्रशासन के अनुसार कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित है। कक्षा 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि कक्षा 10 वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर रहेगी। अभिभावकों से निर्धारित समय-सीमा में आवेदन करने की अपील की गई है। प्रवेश संबंधित विवरण वेबसाइट https://kvsangathan.nic.in/en/admission/ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 1 एवं बालवाटिका 1, 2 एवं 3 (जहाँ लागू हो) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक-https://admission.kvs. gov. in कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 06 वर्ष होनी अनिवार्य है। सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31.03.2026 के अनुसार होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के.वि.सं. के प्रवेश दिशा-निर्देशों 2026-27 के अनुसार किया जाएगा। बालवाटिका-1, 2 एवं 3 में प्रवेश हेतु आयु क्रमशः 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष होगी, जो 31.03.2026 के अनुसार होगी।

2 अप्रैल को टांडा में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, शोभायात्रा रहेगी आकर्षक का केंद्र

नरेन्द्र ठाकुर

टांडा (धार)। नगर की आस्था के केंद्र नरसिंह मंदिर में गत वर्ष के तरह इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। 2 अप्रैल गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्राचीन नरसिंह मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा वही बाहर परिसर में विशाल टेंट लगाया जाएगा जहां पर भोजन भंडारा व्यवस्था रहेगी।

1 अप्रेल सुबह 8 बजे अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगा। नरसिंह मंदिर स्थित प्राचीन चैतन्य हनुमान मंदिर में हनुमान जी का विशेष रूप से मनमोहक चोला श्रृंगार किया जाएगा। जन्मोत्सव के दिन सुबह 6 बजे हनुमान जन्मोत्सव महाआरती उतरेगी तत्पश्चात 8 बजे चल समारोह निकाला जाएगा जो नरसिंह मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगा एवं नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए पुनः नरसिंह मंदिर पहुंचेगा।

चल समारोह बेंड बाजो के साथ निकाल जाएगा जिसमे आदिवासी नृत्य दल,राम दरबार तथा हनुमानजी का बाहुबली स्वरूप एवं वानर सेना कि जीवंत झांकी,नाशिक ढोल, सिर्वी समाज का पारंपरिक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। वही टांडा के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रो में हनुमानजी के कई प्रचीन मंदिर है जहाँ हनुमान जयंती आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। भगवान का विशेष चोरा श्रृंगार किया जाएगा एवं आरती प्रसादी का वितरण भी किया जाता है एवं कई जगह भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उक्त जानकारी हनुमान जन्मोत्सव समिति ने दी है।

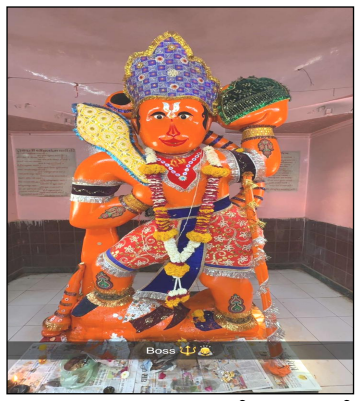

3 मामलों में 55 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। नशा तस्करी के विरुद्ध सतत अभियान के अंतर्गत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, एमपी यूनिट द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थों की जब्ती एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विवरण निम्नानुसार है। दिनांक 22.03.2026 को प्राप्त विशेष खुफिया सूचना के आधार पर P&I सेल, जावरा के अधिकारियों की टीम द्वारा जावरा-उज्जैन हाईवे पर उज्जैन बायपास से लगभग 400 मीटर आगे, नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स शॉप के सामने, जिला रतलाम (म.प्र.) में एक होंडा CD110 डीलक्स मोटरसाइकिल को रोका गया। तलाशी के दौरान लाल-ग्रे रंग की प्लास्टिक बोतल में छिपाकर रखी गई 0.865 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जब्त अफीम एवं वाहन को विधि अनुसार कब्जे में लिया गया है।

दिनांक 22.03.2026 को प्राप्त अन्य विशेष सूचना के आधार पर P&I सेल, जावरा एवं मंदसौर द्वितीय खण्ड की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिगांव माली, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर (म.प्र.) में डिगांव माली-गुर्जर बर्डिया रोड पर एक टाटा टियागो कार को रोका गया। तलाशी के दौरान सह-चालक सीट के नीचे छिपाकर रखे गए हरे-पीले रंग के बैग से 1.827 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इस प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा जब्त मादक पदार्थ एवं वाहन को विधिसम्मत जप्त किया गया है।

पत्रकार को धमकी देने वाले पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने और पेट्रोल पंप सील करने की मांग

नीमच। दशहरा मैदान स्थित फिरोजशाह पेट्रोल पंप के कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश के खिलाफ प्रत्येक उपभोक्ता को केवल 200 का पेट्रोल भरने और फिर उस मामले में खबर को चलाने वाले पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने, अश्लील गालियां बकने के मामले को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है । पत्रकारों ने अनुविभागीय अधिकारी और नीमच कैंट थाना प्रभारी को शिकायत सौंप कर प्रकरण दर्ज करने और पेट्रोल पंप को सील करने की मांग की है ।

मामले में बताया कि पत्रकार संजय यादव विगत बुधवार 25 मार्च 26 को दशहरा मैदान श्री गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद पेट्रोल भरवाने के लिए फिरोज शाह पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां पर पेट्रोल पंप भरने वाले कर्मचारियों द्वारा पेट्रोल भरवाने वाले उपभोक्ताओं से यह कहा जा रहा था कि पेट्रोल की किल्लत है एक बार में केवल

?200 का पेट्रोल भर पाएंगे । मामले को लेकर पहले कर्मचारी से और फिर केबिन में बैठे हुए मैनेजर से विडियो पर सवाल किया कि केवल 200 पेट्रोल भरने का कोई जिला प्रशासन का कोई आदेश आपके पास मौजूद है क्या । पश्चात पत्रकार द्वारा इस संदर्भ में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर एन दिवाकर से बात की गई और मैनेजर से बात करवाई गई उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसको गाड़ी में जितना पेट्रोल भरवाना है भर सकते हैं । मैनेजर के इंटरव्यू वाला वीडियो की खबर बनाकर पत्रकार साथियों ने प्रेषित की। इस बात से बौखला कर 26 मार्च गुरुवार को दोपहर 12.33 पर पत्रकार संजय यादव को पहले 9109345968 से फिर 9131681852 से फोन आया जिस पर सामने वाले ने पेट्रोल पंप से फोन करना बताते हुए कहा कि आपने मेरा वीडियो वायरल किया है अब देखो मैं क्या करता हूं आप मेरा बैकग्राउंड जानते नहीं हो मैं आपको देख लूंगा, फोन पर तीन अलग अलग लोगों ने लगातार धमकियां दी और फिर मां बहन की गालिया देने लगे।

उपरोक्त विषय में आज पत्रकारों ने अनुविभागीय अधिकारी संजीव साहू और कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा को शिकायत पत्र और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंप कर मांग की, की पेट्रोल पंप मैनेजर, कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए साथ ही केवल 200 प्रति उपभोक्ता पेट्रोल भरकर जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने वाले पेट्रोल पंप को सील किया जाए। इस दौरान पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष हरीश अहीर, युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष राकेश मालवीय, पत्रकार अविनाश जाजपुरा, संजय यादव, अब्दुल अली ईरानी, महेश जैन, श्याम शारडा, आनंद अहिरवार, महेंद्र उपाध्याय, विनोद गुर्जर, हेमंत मेहरा, हिमांशु राजोरा, धीरज नायक, विनोद गोठवाल, रामेश्वर नागदा, देव खाताबिया, तबरेज अगवान, बबलू किलोरिया, प्रथम डोडियार, मनीष नायक, पवन राव शिंदे, मोइन शेख, धीरज नायक, आशीष बंग, शानू चौहान, राजा कुरैशी, भावेश मारू सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी गण उपस्थित रहे।

यश पंवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला पंचायत झाबुआ के विरुद्ध लोकायुक्त की कार्यवाही

(संजय जैन सह संपादक)

झाबुआ। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही। आवेदक मांजुसिंह परमार पिता सुरसिंह परमार, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रूपाखेडा तहसील रानापुर जिला झाबुआ आरोपी यश पंवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला पंचायत झाबुआ रिश्वत राशि 10,000

विवरण–आवेदक ग्राम ग्राम रूपाखेडा तहसील रानापुर जिला झाबुआ का रहने वाला है। आवेदक जिला पंचायत झाबुआ में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य करता था। दिनांक 10.03.2026 को आवेदक की सेवा समाप्त करने की सूचना दी गई। जिस पर आवेदक जिला पंचायत झाबुआ जाकर जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आरजीएसए) यश पंवार से मिला तो आरोपी यश पंवार द्वारा आवेदक को डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पुनः ज्वाईनिंग दिलवाने के एवज में 15,000 रू. की मांग की गई। आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। आरोपी यश पंवार, के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अपराध पंजीबद्ध किया गया। **ट्रैपदल**–कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक आनंद चौहान, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक चन्द्रमोहन सिंह बिष्ट, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया।लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

आमजन से अपील है की कोई अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करे तो लोकायुक्त कार्यालय इंदौर एवं दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर सभाग इंदौर पता-मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर-452007 दूरभाष 0731-2533160, 0731-2430100

शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफन को हाईकोर्ट ने फिर फटकारा, 15 दिन में हलफनामा देने का आदेश

शाजापुर। जिले की कलेक्टर को हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाने के साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट ने कहा है- कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है और वो बिना सोचे-समझे आदेश पारित कर देती हैं। मामला एक नाजिर की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश से जुड़ा है। बता दें कि ये तीसरी बार है जब हाईकोर्ट ने शाजापुर कलेक्टर को फटकार लगाई है।

शाजापुर कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार

शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश जयकुमार पिल्लई ने कड़ी फटकार लगाई है। मामला शाजापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी जयंत बघेरवाल की दो वेतनवृद्धि रोकने के साथ ही उसे गुलाना अटैच किए जाने से जुड़ा है। कर्मचारी ने कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट

का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधीश जयकुमार पिल्लई ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर ऋजु बाफना को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कलेक्टर कुछ भी आदेश पारित कर देती हैं, जैसा कि आबकारी अधिकारी के मामले में भी किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कलेक्टर को कानून की जानकारी नहीं है।

15 दिन में हलफनामा देने का आदेश

हाईकोर्ट ने कलेक्टर ऋजु बाफना को 15 दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। इस हलफनामे में कलेक्टर ऋजु बाफना को स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किन नियमों के तहत बिना जांच के दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए।

स्थगन आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और बिना किसी विभागीय जांच के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए।

इन दो मामलों में पहले लग चुकी है फटकार

इससे पहले 30 जून 2024 को हाईकोर्ट ने शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की थी। ये मामला हाट मैदान स्थित भूमि को लेकर था जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर व सीएमओ नगरपालिका ने निजी भूमि पर लगने वाले हाट बाजार को नहीं हटाया था।

प्रकाशक, मुद्रक धवन माहेश्वरी, मालिक गजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा उदयरत्न ऑफसेट,।0/2, दारू गोडाउन के आगे, आगर रोड़, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, 190, विधापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित
संपादक:शानू माहेश्वरी, (9754776006, 7974826006, 8643056464,9575154444) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक समाचार के लिए प्रधान संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के विवादों के निपटारे हेतु न्यायालय क्षेत्र उज्जैन ही रहेगा । समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिमेदार। कानूनी सलाहकार तनुज दीक्षित (अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट)।